मुक्त व्यापार समझौता

प्रश्न पत्र - 3 (समावेशी विकास और संबंधित मुद्दे)

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

- हाल के दिनों में, भारत सरकार सक्रिय रूप से देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की एक विस्तृत श्रृंखला का पालन कर रही है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है ?

- मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता है।
- वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत कम या बिना किसी सरकारी टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, या उनके विनिमय को बाधित करने के लिए निषेधों के साथ खरीदा और बेचा जा सकता है।
- मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है।
- आरम्भ में मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के खिलाफ संघर्ष करने के बाद सरकार ने अब इसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया है।

- ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे विभिन्न देशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कई देशों; जैसे- यूके और यूरोपीय संघ के साथ प्रक्रियाधीन हैं।

बहुपक्षवाद और FTA के बीच संबंध

- GATT के अनुसार "किसी भी अनुबंधित पक्ष द्वारा किसी भी अन्य देश में उत्पन्न होने वाले या वहाँ जाने वाले किसी भी उत्पाद के लिए दिया गया कोई भी लाभ, पक्ष, विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा बिना किसी शर्त के अन्य सभी अनुबंधित पक्षों के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले या नियत उत्पाद के लिए तुरंत प्रदान की जाएगी।

WTO समझौते के प्रावधान

- FTA सदस्य FTA के गठन से पहले मौजूद गैर-सदस्यों के साथ व्यापार पर उच्च या अधिक प्रतिबंधात्मक टैरिफ या गैर-टैरिफ बाधाओं का निर्माण नहीं करेंगे।
- टैरिफ और अन्य व्यापार प्रतिबंधों का उन्मूलन "ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले उत्पादों में घटक क्षेत्रों के बीच पर्याप्त रूप से सभी व्यापार" पर लागू होता है।
- FTA के भीतर व्यापार पर कर्तव्यों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों का उन्मूलन "समय की उचित अवधि के भीतर" पूरा किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ 10 वर्ष से अधिक की अवधि नहीं है
- **तरजीही व्यापार समझौता (PTA):** एक PTA में, दो या दो से अधिक भागीदार टैरिफ लाइनों की एक सहमत संख्या पर टैरिफ कम करने के लिए सहमत होते हैं। उन उत्पादों की सूची, जिन पर भागीदार शुल्क कम करने के लिए सहमत होते हैं, सकारात्मक सूची कहलाती है। इंडिया मर्कोसुर पीटीए इसका एक उदाहरण है। हालांकि, सामान्य तौर पर PTA सभी व्यापारों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** FTA में, भागीदार देशों के बीच पर्याप्त द्विपक्षीय व्यापार को कवर करने वाली वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर दिया जाता है। हालाँकि, प्रत्येक देश, गैर-सदस्यों के लिए एक व्यक्तिगत टैरिफ संरचना बनाए रखता है। भारत- श्रीलंका FTA इसका एक उदाहरण है।
- FTA और PTA के बीच मुख्य अंतर यह है कि PTA में उन उत्पादों की एक सकारात्मक सूची होती है जिन पर शुल्क कम किया जाता है, जबकि FTA में एक नकारात्मक सूची होती है जिस पर शुल्क घटाया या समाप्त नहीं किया जाता है।
- इस प्रकार, PTA की तुलना में, FTA आमतौर पर टैरिफ लाइनों (उत्पादों) के कवरेज में अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन पर शुल्क कम किया जाना है।
- **कस्टम यूनियन:** एक सीमा शुल्क संघ में, भागीदार देश आपस में शून्य शुल्क पर व्यापार करने का निर्णय ले सकते हैं, हालांकि वे शेष विश्व के विरुद्ध सामान्य टैरिफ बनाए रखते हैं। एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया, बोत्सवाना और स्वाज़ीलैंड के बीच दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) है। यूरोपीय संघ भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **कॉमन मार्केट:** कॉमन मार्केट द्वारा प्रदान किया गया एकीकरण सीमा शुल्क संघ द्वारा प्रदान किए गए एकीकरण से एक कदम गहरा है। एक सामान्य बाजार एक सीमा शुल्क संघ है जिसमें श्रम और पूंजी के मुक्त आवागमन की सुविधा, सदस्यों के बीच तकनीकी मानकों का सामंजस्य आदि के प्रावधान हैं। यूरोपीय साझा बाजार इसका एक उदाहरण है।

FTA का महत्व

- टैरिफ और कुछ गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके एफटीए भागीदारों को एक दूसरे के बाजारों में आसान
- बाजार पहुंच मिलती है। देश कई कारणों से मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते हैं।
- निर्यातक बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण की तुलना में एफटीए को तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें गैर-एफटीए सदस्य देश के प्रतिस्पर्धियों पर तरजीह दी जाती है।
- एफटीए स्थानीय निर्यातकों को उन विदेशी कंपनियों से हारने से भी बचा सकते हैं जिन्हें अन्य एफटीए के तहत तरजीह दी जा सकती है।
- एफटीए के बाहर से विदेशी निवेश में वृद्धि की संभावना।

FTA को अंतिम रूप देने में प्रमुख चुनौतियां

जनसांख्यिकीय विभाजन:

ये गैर-टैरिफ मुद्दे भारत के लिए अपने तुलनात्मक श्रम उपलब्धता का लाभ उठाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

गैर-टैरिफ मुद्दों को प्राथमिकता:

वर्तमान में चर्चा के तहत अधिकांश वार्ताओं में, जलवायु कार्रवाई, कार्बन उत्सर्जन और श्रम संबंधी मुद्दों को व्यापार के मुद्दों पर वरीयता दी जा रही है।

संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ:

"गैर-आवश्यक वस्तुओं" पर आयात शुल्क बढ़ाने की योजना जैसे कदम सरकार पर केवल संरक्षणवादी होने के आरोप को उजागर करेंगे।

1991-92 के बाद पहले दो दशकों में टैरिफ दरों में भारी गिरावट देखी गई।हालांकि, इस प्रवृत्ति को सत्तारूढ़ सरकार द्वारा उलट दिया गया है, औसत लागू आयात शुल्क वास्तव में बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई **हैं।**

मंदी की स्थिति:

ये संभावित रूप से साझेदार देशों को गैर-टैरिफ संरक्षणवादी उपायों को ट्रिगर करने की पेशकश कर सकते हैं क्योंकि विकसित राष्ट्र मंदी की स्थिति में हैं।

पर्यावरण के मुद्दे:

अमेरिका जैसे विकसित देशों ने गैर-टैरिफ-संबंधित मुद्दे के रूप में पिघले हुए स्टील के निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे को उठाया है।

भारत ज्यादातर लौह अयस्क से उत्पन्न स्टील का उत्पादन करता है जो खनन से आता है।

अधिकांश विकसित देशों ने इसे स्क्रैप से उत्पन्न करने के तरीकों का सहारा लिया है जिसके परिणामस्वरूप कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इस प्रकार, कार्बन समायोजन कर लगाया जा सकता है।

GSP (वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली):

वर्तमान में हम GSP से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन यदि वे श्रम या पर्यावरण का हवाला देकर गैर-टैरिफ बाधा में आते हैं, तो यह मानकों, समायोजन, बाल श्रम का हवाला देते हुए एक मुद्दा बन जाता है।

भारत नवंबर' 1975 से अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम का लाभार्थी रहा है, जिसके तहत लाभार्थी देशों को शुल्कों के अतिरिक्त बोझ के बिना अमेरिका को हजारों उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र:

यूरोपीय संघ ने CBAM को 2026 से लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली उत्पादन जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया है।

यहाँ, यूरोपीय संघ के आयातक उस कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदेंगे जिसका भुगतान यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के तहत किया गया था।

आगे की राह

KARMANYEVADHIKARASTE MA PHALESHU KADACHANA
THE STUDY
An Institute for IAS

बाधाओं को कम करना: ऐसे समय में जब कंपनियां चीन से अलग होने की सोच रही हैं तथा चीन प्लस वन रणनीति का अनुसरण कर रही हैं, तो भारत को व्यापार के लिए बाधाओं को कम करना चाहिए एवं सक्रिय रूप से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना चाहिए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न - भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने के लिए व्यापार की बाधाओं को कम करना चाहिए। विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गयी पहल के संदर्भ में चर्चा कीजिए।